[श्री नवल किशोर शर्मा]

की उम्मीद बंधी तो सभी सरकारी घोषणाओं को ताक पर रख कर इन अंशकालीन संवाददाताओं को हटा दिया जिन में से एक नव-भारत टाइम्स ने 25 साल पुराने संवाददाताओं की छंटनी करने का निर्णय ले लिया और उन की छंटनी कर दी। यही हाल अन्य बड़े अखबार समूहों का भी है जिस से देश में अंशकालीन संवाददाताओं का भविष्य अन्धाकारमय हो चला है।

अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले में गंभीरता से कार्यवाही करें जिस से अंशकालीन संवाददाताओं की बर्खास्तगी बहाल हो तथा पालेकर ट्रिब्यूनल का लाभ इन संवाददाताओं को मिल सके।

(iii) CONSTRUCTION OF A BRIDE OVER GHAGRA JOINING BARABANKI AND BAHRIACH DISTRICT, UTTAR PRADESH

श्री रणवीर सिंह (कैसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच क्षेत्रों में बाढ़ के कारण हर समय जान और माल की हानि का जो खतरा बना रहता है, उस को देखते हुए काफी समय से यह मांग की जाती रही है कि योजना आयोग इस सम्बन्ध में कुछ दीर्घकालिक उपाय करे। जब एक तक भारत सरकार इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम नहीं उठाती तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच जिले अत्यधिक पिछड़े हुए जिले हैं। इसलिए भारत सरकार बाढ़ की समस्या का हल निकालने और साथ ही इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की दोहरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रभावी उपाय कर सकती है। इन जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने और वहां व्याप्त असन्तुलन को समाप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय यह होगा कि यहां यातायात के साधन उपलब्ध कराये जायं।

बहराइच जिले में बहराइच और बाराबंकी को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर कोई पुल न होने के कारण इन क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित नहीं किए जा सके। सभी प्रकार का कच्चा माल यहां उपलब्ध है किन्तु परिवहन की कठिनाई के कारण प्रगति रुकी हुई है।

अनेक बार आश्वासन दिए गए हैं किन्तु कई बार योजना आयोग और कई बार परिवहन मंत्रालय एक न एक बहाना बता देता है। लोगों का धैर्य समाप्त हो चुका है। बार बार की बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के लोगों को निरन्तर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विनाशकारी नदी ने मेरे क्षेत्र को दो भागों में बांट कर रख दिया है। आखिर लोग कब तक इंतजार करें ?

घाघरा घाट पर पुल बन जाने से बहराइच, गोंडा, बाराबंकी और लखनऊ जैसे अनेक जिलों में सम्पर्क स्थापित हो जायगा और उनका विकास हो सकेगा। साथ ही इस से लोगों की कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी। भारत सरकार के योजना आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से अविलम्ब इस पुल का निर्माण करवाना चाहिए।